THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2-5 were added to the Bill.*
*Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): We shall now take up the Special Protection Group (Amendment) Bill, 2002.

---

**THE SPECIAL PROTECTION GROUP (AMENDMENT) BILL, 2003.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Special Protection Group Act, 1988, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I may only reiterate in the beginning that the Special Protection Group Act was passed in 1988. And within a period of ten years, it has already been amended thrice. It was amended in 1991 because, to begin with, when this specialised agency for the protection was...(*Interruptions*)...

**श्री लालू प्रसाद** (बिहार): महोदय, मैं पोइंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2003 को पढ़ लीजिए। एक तरफ एक्स प्राइम-मिनिस्टर को कहा गया है कि एक साल तक पद से हटने के बाद, त्याग पत्र करने के बाद उनको और उनके परिवारजन को एस0पी0जी0 ग्रुप मिलेगा और फिर वहीं पर सरकार ने अपना अधिकार ले रखा है दूसरे खंड मे कि एक साल बाद सरकार देख लेगी कि इनके ऊपर खतरा है या नहीं है। यह बात बहुत गलत है। आप यहां स्पेसिफिक लाइए कि एक साल रखना है तो एक साल रखना है, फिर अपने हाथ में क्यो रखते हैं। ऐसा देखा जाता है कि......(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री पी0 प्रभाकर रेड्डी)**: बिल पर डिस्कसन होने दीजिए फिर बाद मे डिसाइड होगा।

**श्री लालू प्रसाद:** ऐसा कहीं बिल आता है । क्यों इसमें यह अधिकार दिया जाए?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी:** 1988 में यह जो एक्ट बना था वह एक स्पेशलाइजेशन एजेंसी के लिए बना था । स्पेशलाइजेशन एजेंसी बनाई थी कि प्रजेंट प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जब थ्रेट थी तो प्रोटक्शन के लिए स्पेशल एजेंसी बनाई थी। लेकिन उसको 1991 में, 1994 में, 1999 में अमेंड करना पड़ा। 1991 में जब अमेंड हुआ तो वह इस वजह से अमेंड हुआ क्योंकि यह महसूस किया गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी थ्रेट है। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट परसेप्शन है तो उनको भी एस0पी0जी0 कवर प्रोवाइड किया जाए और 1991 में यह कवर देना शुरू हो गया for the former Prime Ministers also for a period of five years. But, then, again, it was felt that instead of five years, it should be extended for ten years. So, in 1994, it was extended for ten years. And, in 1999, when it was extended, it was felt that after ten years also, the threat perception may be there, and they may need this protection from the specialised agency, the Special Protection Group. So, after this amendment, which was made in 1999, it has now come to stay that even after ten years, it will be provided on the basis of the threat perception to be assessed every year. Of course, the assessment period will not lapse after 12 months. Within 12 months, it will be assessed between two consecutive assessment years. Even after ten years, if the threat perception exists, then, it will be provided. This is the Act as it now stands.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair

I have come before this House for consideration of the Amendment Bill; when it has been accepted that every year it has to be assessed. We know that in the case of the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and her family members, for the last four years since 1999, it has been extended year after year because the whole nation knows, and the Government is conscious and cognisant of the fact that the threat perception is always very high in the case of Mrs. Sonia Gandhi and her immediate family members. So, this has been extended since 1999, up till now. Now, this present amendment is only for the purpose, that instead of having five years or ten years, it should be simply that in the case of former Prime Ministers and their immediate family members, it should be assessed every year. And, on the basis of threat perception, it will go on extending. This cover will continue to be provided to them. Supposing, there is now no threat perception and the SPG cover is to be withdrawn. For that, normal provisions are there, but not in this Act. After the SPG cover has been withdrawn, assessment with respect to X, Y, Z or Z plus categories is done

every year, in the case of people who have been facing threats and whose family members have been facing threats. Our former Prime Ministers faced bullets from the militants. So, the only thing is, there should be a threat from militants or from any other source. The threat should be continuing and that it should be grave. In that case, not only the former Prime Ministers, but, even his or her immediate family members would be provided the proximate cover. Sir, these are, in nutshell, the amendments which have been brought. Of course, consequential amendments are there, as far as nomenclature of certain officials is concerned, but that is not material. With these words, I propose that this Bill may be taken into consideration and passed by this House.

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।**

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने जो सेक्योरिटी सीनेरियो है, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, वे बहुत गंभीर हैं। देश को आज न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी शक्तियों से खतरा है- वह चाहे लिट्टे हो, चाहे सीआईए हो, चाहे आईएसआई हो। इसके साथ-साथ देश के अंदर जो विघटनकारी आतंकवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों से खतरा है उससे हम सब परिचित हैं।

इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि वीआईपीज़ की सेक्योरिटी का ध्यान रखा जाना आवश्यक है और यह जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश का सेक्योरिटी सीनेरियो बहुत गंभीर है जिसके बारे मे ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने कंसर्न जाहिर की है और कुछ सुझाव भी दिए हैं और वह हमारे सुरक्षा एजेंडे मे सर्वोच्च स्थान पर है, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर की सेक्योरिटी की बात हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो, चाहे मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट की सेक्योरिटी की बात हो, चाहे अन्य लोगो की सेक्योरिटी की बात हो, जो समय-समय पर विभिन्न स्थानो पर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया करते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रश्न हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री का प्रश्न है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री केवल एक व्यक्ति नही होता है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ-साथ जहां तक मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट का प्रश्न है, वह जन प्रतिनिधि होने के साथ-साथ उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस क्षेत्र की समस्या है, वह उस समस्या को निर्भीकता से उठाता रहे, ऐसी लोगों की अपेक्षा होती है। अभी हाल ही मे ललित माकन की हत्या के संबंध में जो एक-दो दिन पूर्व निर्णय हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य मे मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात उभर कर आई थी कि जिस दबंगता से वह आतंकवादियों और विघटनकारी शक्तियो का पर्दाफाश करता था, उसकी जो हत्या हुई वह उसी परिप्रेक्ष्य मे हुई। चूंकि यह बिल केवल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध मे है इसलिए मैं सीमित

दायरे में एसपीजी जो इन लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए उसके विषय में ही आज कहना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, वह निर्भीकता से, दबंगता से, निडरता से, दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ राष्ट्र-हित में निर्णय ले सके, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेते समय उसके सामने यह प्रश्न-चिह्न नहीं होना चाहिए कि वह जो राष्ट्र-हित में निर्णय ले रहा है उसकी प्रतिक्रिया देश और विदेश की विघटनकारी शक्तियों में क्या रहेगी और उसे क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा? न केवल उसकी जान को खतरा होगा बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की जान को भी खतरा हो सकता है। उनके बचाव की जिम्मेदारी सरकार की हो जाया करती है जो समय-समय पर बनी रहती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां सरकार की हो जाती है, उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पुराने समय से ऐसी व्यवस्था रही है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के राज में जब उसने आक्रमणकारी हूणों के खिलाफ कुछ कठोर निर्णय लिए थे तो उस समय चाणक्य ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे राजा की सुरक्षा का प्रबंध राजकोष की ओर से किया जाना चाहिए और प्रजा को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा राजा जो समय-समय पर ऐसे कठोर निर्णय राज्य के हित में लिया करता है उसकी सुरक्षा का प्रबंध राजकोष से किया जाए। यह कहा जा सकता है कि इससे फंड की एवेलेबिलिटी का क्या होगा? फंड की कमी है, या एसपीजी परसोनल की कमी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो निर्णय समय-समय पर प्रधानमंत्री जी लिया करते हैं, दरअसल वे राष्ट्रहित में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रजा का भी यह दायित्व हो जाता है और साथ ही साथ सरकार में बैठे हुए लोगों या विपक्ष में बैठे हुए लोगों की यह जवाबदारी और जिम्मेदारी हो जाया करती है कि वे व्यापक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में अपने कार्य का निर्वहन करें। मान्यवर, इतिहास इस बात का गवाह है क्योंकि मैं यहां एसपीजी के संबंध में चर्चा कर रहा हूं, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि यदि हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमारे देश के दो यशस्वी नेता विघटनकारी शक्तियों के शिकार हुए हैं। एक जो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर थीं। उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। दूसरे, वे राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए लिट्टे एजेंसी और अन्य एजेंसी की गतिविधियों के शिकार हुए और उन्हें अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। इसके अतिरिक्त हमारे देश में ऐसे भी कई नेता रहे हैं, कई ओहदेदार रहे हैं जिन्होंने इन विघटनकारी शक्तियों से जूझते हुए या तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया या उनकी जान को खतरा है। चूंकि यह सारी स्थिति हमारे देश की सिक्योरिटी की है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तरफ उन लोगों को सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, जो कि इस प्रकार के कठोर निर्णय लिया करते हैं, अलग-अलग ओहदों पर हैं। चूंकि यह बिल जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से संबंधित है, मुझे एकाएक वह भावुक क्षण याद आ जाते हैं जब इसी सदन में राजीव गांधी की हत्या का उल्लेख किया गया था। उस समय सभी माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि राजीव गांधी की सिक्योरिटी लैप्स की जांच करने के लिए एक कमीशन का गठन करना चाहिए। वर्मा कमीशन का गठन हुआ और वर्मा कमीशन ने जो फाइन्डिंग्स उस समय ली,

मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। क्योंकि केवल थ्रेट परसेप्शन का जिक्र किया है। जस्टिस वर्मा कमीशन जिस नतीजे पर पहुंचा, मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा :-

Justice Verma Commission came to the conclusion that had the SPG cover not been withdrawn, the assassination of Shri Rajiv Gandhi could have been averted.

The observation of the Verma Commission contained in para 9.14 of its report says, "Justice Verma noted that the threat to Rajiv Gandhi remained undiminished even on ceasing to be the Prime Minister."

At para 9.16, the Verma Commission of Enquiry observes, "Suitable alternative arrangements were not made and fresh assessment of threat was not taken."

प्रश्न इस बात का उठता है कि जब हम एक तरफ यह कहते हैं कि थ्रेट परसेप्शन को दृष्टिगत रखते हुए प्रोक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी तो इतिहास इस बात का गवाह है कि थ्रेट परसेप्शन पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लोगों के लिए नहीं लिया गया था। यह आब्जर्वेशन किसी राजनीतिज्ञ का नहीं था, यह आब्जर्वेशन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था । यह आब्जर्वेशन उस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का है, जिस वर्मा कमीशन के गठन के संबंध में राजनीतिक पार्टियों ने ऊपर उठकर, एक मत से मांग की थी कि जो वर्मा कमीशन का आब्जर्वेशन है, उसको गंम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, गृह मंत्री जी ने अपने प्रश्न क्रमांक 2839 में, इसी सदन में, 19 अप्रैल, 2000 को जो उत्तर दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार का थ्रेट परसिप्शन बहुत हाई है और उनको एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न केवल इस बात का नही है बल्कि प्रश्न इस बात का है कि थ्रेट परसेप्शन का आधार क्या हुआ करता है? थ्रेट परसेप्शन किस आधार पर लिया जाता है, यदि मैं उसकी तरफ नजर दौड़ाऊं तो मैं आपके जरिए गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि लोवर लेवल पर सीनियर आफिसर्स का प्रोटेक्टिव रिव्यूव ग्रुप बनता है, यह एक रिपोर्ट सिक्योरिटी कैटेग्राइजेशन कमेटी को प्रस्तुत करते हैं। उस कमेटी में पी.एम.ओ. का एक ज्वाइंट सेक्रेट्री हुआ करता है, एक होम सेक्रेट्री हुआ करता है, एक स्पेशल सेक्रेट्री हुआ करता है । आई.बी. का या तो डायरेक्टर हुआ करता है या ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करता है । सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन को आंकने के लिए यही व्यवस्था उस समय भी थी । राजीव गांधी जी का सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई था । उस समय के कैबिनेट सेक्रेट्री का यह ऑब्जर्वेशन था । यह उस समय के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हाई था । फिर भी इसे नजरअंदाज करते हुए एस.पी.जी. विदड्रा की गई । एस.पी.जी. विदड्रा की गई और जो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए थी वह प्रदान नहीं की गई । थ्रेट परसेप्शन भी नहीं लिया गया । यह हम लोगों का अनुभव रहा है । मैं सोचता हूं कि जब इस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें अन्य क्राइटेरिया के बारे में विचार करना चाहिए । मान्यवर, इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है ।

एस.पी.जी. अमेंडमेंट बिल, 2003, पेज 2, क्लॉज 2 की पांचवी लाइन के साथ-साथ यह इन्सर्ट किया जाना चाहिए - जो "सी" पार्ट है, उसमें जो क्राइटेरिया की बात है - Immediate family members of a former P.M., who have been affected by terrorist/militant acts." मैं सोचता हूं कि थ्रेट परसेप्शन के साथ-साथ हम इसका भी आकलन करें कि ऐसे कौन से परिवार हैं जिन परिवारों से प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन परिवारो को आतंकवादी और विघटनकारी ताकतों का शिकार होना पड़ा है । क्या उन परिवारों को थ्रेट परसेप्शन के साथ-साथ एस.पी.जी. सिक्योरिटी प्रदान करने के संबंध मे भी हमें विचार नहीं करना चाहिए ?

मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उस सदन मे और यहां भी - माननीय मंत्री जी जो भी दूसरे सदन मे कहें, क्योंकि मंत्री कहता है तो उसका उल्लेख हो सकता है - इस बात का जिक्र किया है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके इमिजिएट फैमिली मैम्बर्स का थ्रेट परसेप्शन हाई है । इसलिए हम इस क्राइटेरिया को तय करते समय यह भी विचार करें कि एस.पी.जी. प्रदान करते समय, थ्रेट परसेप्शन के अलावा उन परिवारो पर भी विचार किया जाएगा जिन परिवार के लोगो ने इस देश का नेतृत्व किया है, जिन्होंने नेतृत्व करते समय देश हित में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुछ निर्णय लिए हैं । थ्रेट परसेप्शन के साथ-साथ उन परिवारो को एस.पी.जी. सिक्योरिटी कंटीन्यू करने के बारे में हम जो क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, यदि हम इस पर विचार करेगे तो मैं सोचता हूं कि यह एक सामयिक कदम होगा । मान्यवर, यह मेरा आपके जरिए आग्रह है । आज केवल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवारजनों की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है । प्रश्न इस बात का है - जैसे मैंने अपनी बात आरंभ करते हुए कहा था कि समय-समय पर महत्वपूर्ण पदो पर बैठे हुए लोग, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की हुआ करती है । इस सदन मे बैठे हुए जब हम इस प्रकार के बिल प्रस्तुत करते हैं, चाहे हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें तब हम लोगों की भी यह जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है कि यहां यह भी विचार करें कि जिन लोगों को समय-समय पर थ्रेट मिलती रहती हैं उनकी सिक्योरिटी का भी प्रबंध हो । साथ ही उन पदों पर जो महान् व्यक्ति विराजमान रहे हैं, यशस्वी नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी पर भी विचार करें । प्रश्न इस बात का उठता है, जैसाकि मैंने कहा था कि ऐम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स मे यह बात कही गई है कि सिक्योरिटी पर्सोनल्स की कमी की वजह से समय-समय पर इस प्रकार के निर्णय लिए गए । मैं यह मानता हूं कि सिक्योरिटी पर्सोनल्स की जो सैंक्शन्ड स्ट्रेन्थ है, उसके मुकाबले उनकी स्ट्रेन्थ की जो अवेबिलिटी है, वह कम है । फिर भी यह देखा जाए कि हमें वरीयता और प्राथमिकता किन-किन चीजों को देनी चाहिए ।

मान्यवर, देश के नेताओं की हत्याएं होने लगी हैं । मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश के प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी बजनी प्रारंभ हो गई है । देश की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि देश मे स्थायित्व बना रहे । देश के नेता समय-समय पर देश हित में कठोर निर्णय लेते रहें । उन्हें अपने परिवार की चिंता न हो, उन्हें अपनी जान की चिंता न हो, इसके लिए आवश्यक है कि मेरे इस संशोधन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और जब रिप्लाई देंगे तो इस बिंदु के प्रकाश में भी वे इसका भी उल्लेख करेंगे । मैं सोचता हूं कि जिस मंशा से यह बिल समय-समय पर लाया जाता रहा है - यद्यपि मंत्री जी ने कहा है कि इससे पहले 1988 में लाए थे और 1988 से 1999 के

बीच इसे तीन बार संशोधित किया है । 1999 में हमने यह व्यवस्था की थी कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर और उसके इमिजिएट फैमिली मैम्बर्स के लिए भी यह रहे । तो यह निरंतरता बनी रहे। इसके पीछे जो भाव है, जो भावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मान्यवर, जब इस प्रकार का प्रोविजन हम लोग ध्यान में लायेंगे तो मैं सोचता हूं कि उससे इस बिल को लाने के पीछे जो मकसद है, जो ध्येय है, वह पूरा हो सकेगा ।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा कि यदि प्रधानमंत्री पद-पर बैठे हुए लोग, चाहे वे प्रधानमंत्री पद पर रहे हों या प्रधानमंत्री के पद से हट गए हों, ईश्वर न करे, जब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो प्रश्न यह नहीं उठता है कि अनहोनी किस कारण से हुई, बल्कि उसके लिए हम भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं । यदि इस प्रकार के निर्णय राजकीय कोष के पैसे को ध्यान में न रखते हुए हमने लिए और ऐसे निर्णय लेने मे हमने सहायता की, तो मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि जिन राष्ट्र के सपूतों ने राष्ट्रहित को मद्देनज़र रखते हुए कठोर निर्णय लिए हैं, हम भी इस राष्ट्र के नागरिक होते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे । क्योंकि केवल वह व्यक्ति, जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियो का शिकार होता है, यह ठेस केवल उसको नहीं पड़ती है बल्कि उसके निर्णय पर पड़ा करती है और उसकी नीति पर पड़ा करती है । इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार के निर्णय ले । अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश मे ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है ? मान्यवर, मैं केवल अपने देश की ही बात नहीं करूंगा। अब्राहिम लिंकन, जो यू.एस.ए. के अग्रणी नेता थे, उनका जब असैसिनेशन किया गया तो हम लोगों ने इस बारे में विचार किया । इसी प्रकार मॉर्टिन लूथर किंग की जब हत्या की गई तो उस समय भी हम लोगों ने विचार किया। लेकिन अफसोस है कि महात्मा गांधी की जब हत्या की गई तो हमने इस बारे मे विचार नही किया और इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई तो हम लोगो ने विचार नहीं किया । लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्हे इस प्रकार के निर्णय समय-समय पर लेने पड़ते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रकार की स्पेशल सैक्योरिटी का प्रोविज़न होना चाहिए जो कि स्पेशली ट्रेंड हो । 1988 में हमने यह निर्णय लिया था और एसपीजी का बिल लाए थे । उसके बाद समय और अनुभव के आधार पर हम लोग संशोधन लाते रहे । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय और अनुभव के आधार पर, न केवल थ्रैट परसैप्शन के दायरे में हम अपने आपको सीमित रखें बल्कि समय और अनुभव के आधार पर हमें यह भी देखना होगा कि वे कौन से परिवार हैं, जिन परिवारों के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और वे आतंकवादी या उग्रवादी शक्तियों के शिकार रहे हैं, उनके बारे मे क्राइटीरिया तय करते समय एसपीजी की सैक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए हमको विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा आपके जरिए आग्रह है । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपना जब उत्तर देंगे तो एक व्यापक दृष्टिकोण में उत्तर देंगे ।

मान्यवर, जहां तक एस.पी.जी. पर्सनल्ज़ का सवाल है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां हम लोग इन लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि ये वीवीआईपी की सैक्योरिटी का सही ढंग से इंतज़ाम करें, एस.पी.जी. को भी समय-समय पर दिक्कत होती है और उन्हें अपनी जान को हथेली पर रख कर अपने प्रोटैक्टी की जान बचाने के लिए आगे आना पड़ता है, तथा उनकी भी जान जाती है वहां उनके परिवार के लिए भी हम कुछ वेलफेयर स्कीम्ज़ पर विचार करें ताकि

वे भी निर्भीकता से अपने प्रोटैक्टी की मदद कर सकें । इस बारे में माननीय मंत्री विचार करेंगे ऐसा मेरा आपके जरिए आग्रह है ।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एस.पी.जी. अमेंडमेंट बिल, 2003 लाए हैं उसमें जो संशोधन मैंने जिस भावना से रखा है उसी के प्रकाश में वे इस प्रकार के निर्देश अपने अधिकारियों को देंगे कि जो मापदंड निर्धारित किया जाएगा उसमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने को माननीय श्री सुरेश पचौरी जी की भावनाओं से पूरी तरह सम्बद्ध करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं वहां तक तो नहीं जाता कि वह कौन सा शासन था जो महात्मा गांधी को सुरक्षित नहीं रख पाया या इंदिरा गांधी जी को सुरक्षित नहीं रख पाया या राजीव गांधी जी को सुरक्षित नहीं रख पाया, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी की सुरक्षा के लिए जो शासन कटिबद्ध है ...... । इस की प्रामाणिकता और एफिसिएंसी इसी बात से प्रमाणित होती है जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी नितांत निर्भीक रूप से अपनी पूरी भावना को सारे देश और संसार मे व्यक्त कर पा रही हैं । महोदय, यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि उन की ऐसी सुरक्षा बनी रहेगी, इस में मुझे कोई संशय नहीं है । शायद ऐसी जितनी चिंता उन के पक्ष के लोगो की है उस से कहीं अधिक चिंता प्रत्येक शासन की होगी क्योंकि अगर कमी उन की सुरक्षा में कमी रह जाती है तो उस का ब्लेम शासन पर ही आता है । इसलिए शासन उस से कहीं अधिक इस बात के लिए चिंतित होगा और उसे रहना चाहिए कि जो भी हमारे देश के प्रमुख नेता हैं, वे किसी भी तरह के खतरे से नितांत रूप से बाहर रखे जाएं ।

महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, वह संभवतः इसलिए कि इधर कुछ चेंजेज के कारण प्रधानमंत्री इतनी जल्दी-जल्दी बदले कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या बहुत बढ़ गयी और एस0पी0जी0 की संख्या वही 3 हजार रही । यही नहीं एस0पी0जी0 में सलेक्शन के लिए स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशंस रखी गयी हैं जैसे किस प्रकार से जवान उस में भर्ती किया जाएगा, उसी का यह नतीजा है कि जितने जवान उस की भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, उस संख्या के 25-30 प्रतिशत ही आ पाते हैं । इस के अलावा उस फोर्स के लिए उम्र का एक टाइम-फ्रेम है और बाद में वह जवान वापिस चला जाएगा । महोदय, आज वहां तकरीबन 600 वेकेंसीज हैं । यह बात अपनी जगह है, लेकिन आज सुबह वेकेंसीज की बात हो रही थी कि सैकड़ो वैकेंसीज जजेज मे उस जगह हैं जहां कि सब को दिख रहा है कि हां उन को जज बनाया जाना चाहिए और निश्चित है कि उस जज को उस वक्त रिटायर करेंगे ।

महोदय, ऐसी भी स्थिति आई है कि चन्द्रशेखर जी ने कहा है कि मुझे सेक्युरिटी नहीं चाहिए । माननीय वी0पी0 सिंह जी कहते हैं कि मुझे सेक्युरिटी क्यों दे रखी है ? लेकिन एस0पी0जी0 एक्ट के तहत उन को सेक्युरिटी देनी ही है और उन के अकेले कहने से कोई शासन सेक्युरिटी नहीं हटा सकता । प्रत्येक शासन को प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए सेक्युरिटी थ्रेट के सूत्रों के आंकलन के उपरांत ही सेक्युरिटी देनी है, लेकिन जिन की सेक्युरिटी थ्रेट कम है, उस के लिए कम करने का अधिकार मिले, उन की सीमा तय करे कि इस प्रकार की सेक्युरिटी

से काम चलाया जा सकता है तो एस0पी0जी0 को विदड्रा कर सकते हैं । इसलिए यह विधेयक लाया गया है । इस के अलावा अगर एस0पी0जी0 के पर्सोनल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया जाएगा और उन्हें उन की ट्रेनिंग और उन की मशक्कत का समय नहीं मिलेगा तो उन की एफिसिएंसी घट जाएगी । जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, वह सिर्फ इसलिए है कि एक साल की सीमा बंधे और उस के अंदर-अंदर यह सुविधा उपलब्ध रहे ।

महोदय, आज माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय सोनिया जी, माननीय नरसिंह राव जी, माननीय गुजराल जी और माननीय देवेगौड़ा जी को यह सुविधा उपलब्ध है ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : माननीय चन्द्रशेखर जी को है ।

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल** : उन को शायद इस वक्त नहीं है । हो सकता है गलती हो । तो उस में समय सीमा बांधी गयी है । इस का अर्थ यह नहीं है कि सरकार वह विद्ड्रा करने को बाध्य है । यह जिम्मेदारी सरकार की है और कोई सरकार भूल करेगी अगर वह अपनी इस मौलिक जिम्मेदारी से जरा भी शिथिल होगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय पचौरी जी जो अमेंडमेंट लाए हैं, वह विधेयक में पूरी तरह से ऑलरेडी हैं । अब उस में क्या अंतर है, यह मैं वास्तव में नहीं समझ पाया क्योंकि सेक्शन "ए" और "बी" में वे सारी चीजें लिखी हैं और यह भी लिखा है "कंटीनुइंग थ्रेट", फिर भी आप अमेंडमेंड लाए हैं तो उस की कोई वजह रही होगी वरना वह तो आलरेडी है । इस तरह एस0पी0जी0 का काम सुचारु रूप से हो सके, एफिसिएंसी से हो सके ...और सरकार सतत इस बात के लिए सतर्क रहे कि जो भी इस देश के राष्ट्रीय नेता हैं उन पर फिर कभी ऐसा संकट न आए, जैसा अनफोर्चुनेटली पास्ट में हो चुका है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को यूनेनिमसली सपोर्ट करने के लिए पुरजोर प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद ।

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Special Protection Group Bill, 2003 as passed by Lok Sabha. Sir, as mentioned by the hon. Minister, this Act came into force in the year 1983. In the last 13 years, it was subjected to amendments three times. In the year 1991, the first amendment came for covering the former Prime Ministers. In the year 1994, the period of five years was extended to 10 years. Again, in the year 1999, the period was further extended beyond 10 years. Sir, the present amendment is for reducing the period to one year for the former Prime Ministers and it is on the basis of threat perception. A review will be made on case-to-case basis and the review will be made every year.

Sir, at the outset, I welcome the Bill and extend our support. Sir, if you see the history of the world and the history of our nation, a number of top leaders have become the victims of the acts of terrorism. They have become targets, not because of any personal rivalry or animosity but because of the decisions they had taken for the welfare of the country and for the common good of the people.

When we are talking about providing security to the Prime Ministers and former Prime Ministers, in my opinion, there should not be any other consideration. We should rise above the party lines and then we must provide protection. It is the duty of the entire nation to provide protection to such personalities.

Persons who have occupied the highest positions in our country - the largest democracy - need to be protected. They are not ordinary personalities. Their name and fame is not just confined to our country, all the people outside the world know about them, and if anything happens to them, it will be a sense of shame to the entire nation. Therefore, Sir, it will not only send shock waves in the country but it will send wrong signals to the entire world. The people outside the world will suspect our security and safety system.

Sir, today the threat to VIPs is more acute than what it was ten years back or, for that matter, couple of years back. Therefore, my suggestion is that anything we do, any amendments we bring, that should be to strengthen the law rather than to dilute it.

It is not the question of how much money we are spending. Hon. Minister while giving reply to this debate in the Lok Sabha said that it is costing about Rs. 75 crores to the country. Sir, I am glad that he said that it is not the question of money and this amendment is not brought forward to save the money. But the funny part is, he says that there is a dearth of personnel. We are a nation of one billion people and we cannot train thousands of SPG people. I do not think that this is a sound argument. The argument is a bit hollow.

Sir, all of us are aware that there is great danger from hard-core terrorists who are being aided and abetted by our neighbour. People in high offices have to take hard decisions, particularly against hard-core

**4.00 p.m.**

terrorists. So, Prime Ministers, after demitting their office, continue to be threatened by the terrorists.

Sir, one important point, which I would like to raise, is that all the time we are talking about providing security. Security will take place when there is a threat perception. But my point is why not we beef up our intelligence system. We see the case of the United States of America. The United States of America, after September 11 attack, have beefed up the entire intelligence system. They have allocated billions of dollars for strengthening the intelligence system. Why cannot we do it in our country - whether our financial position is good or not? We allocate thousands of crores of rupees for Defence.

In my opinion, today we have more internal security threats than external security threats. If we have to divert funds from the Defence to strengthen the intelligence system, I suggest that the Government should do it.

Sir, apart from the Prime Minister and ex-Prime Ministers, there are other important functionaries like the Deputy Prime Minister who is the most threatened person today. Even he has got more threats to his life than the Prime Minister. There are Chief Ministers and many other VIPs who are occupying high positions, who are under threat. Even they should also be given protection. It is not a question of money; it is a question of reputation. With these words, I support the Bill.

SHRI C.O. POULOSE (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the terrorists and extremists are making their base widespread. The mafia gangs and other criminals are also expanding their base. Some of them have a national network and some others have international connections. This is the situation in India and this is the situation the world over. We all know, these terrorist groups have assassinated many of the world leaders. We also have the experience of loosing many of our national leaders. How can we contain the activities of the terrorists and extremists who are expanding their base? That is a different question. Anyhow, there is a threat. So we need to take measures to protect our national leaders. The present Bill is for giving protection to the ex-Prime Ministers. They need to be protected with all the force in command.

Now the Government has proposed to have an annual assessment of the threat perception. It should be done impartially. The Government should evolve a method to have an impartial assessment of the threat perception. Whatever money is needed, that should be provided. We should provide sufficient protection to our national leaders who are under threat. I support the Bill whole-heartedly.

I would like to say one thing more. The SPG is being given training. It is a well-trained force. I would like to say that these personnel also have got threat to their lives while protecting the ex-Prime Ministers and other VIPs. Their lives are also in danger. The Government should provide protection to the SPG personnel also. The Government should evolve some methodology. They should provide protection not only to the SPG, but also to the security staff of Parliament and other security people who are working in Government concerns. With these words, I support this Bill. Thank you.

SHRI C.P.THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to say a few words on the Bill and the amendment that has been brought forward. Clause (a) of Section 2 says, "the threat element from any militant or terrorist organisation or any other source", as far as the expression "any other source" is concerned, it is not defined in the original Bill. It is not mentioned in the original Bill. Now, the expression "any other source" has it been included? I want a clarification from the hon. Minister as to what is meant by "any other source". If it is defined clearly, we can understand the impact as it is. I would like to say only one thing on the amendment, that has been brought by my learned friend, Shri Suresh Pachouri. I fully support this. If clause 3 is included, it becomes mandatory on the part of any Government. If the Prime Minister dies or the ex-Prime Minister dies, his family members are automatically entitled to all the protections, in spite of asking them before the authorities. If it is included, it will be better as it is. I would like to submit that it has not been defined as to what is meant by "threat". We can refer to the English dictionary; that is different. My humble submission to the hon. Minister is, if it is defined what is meant by "threat" to the person, or, to the property, or, kidnapping, or ransom, or some other thing, if it is clearly defined in the Act itself, it will be better to ascertain what sort of threat is there in respect of other parties. This should be taken into consideration. That is my main submission in regard to this Bill.

As my friend just now said, several people throughout the world have lost their lives for the sake of the nation. Abraham Lincoln was assassinated because he put his signature on the ground of social liberty. Mahatma Gandhi was assassinated because some people thought he was responsible for the separation of India. Martin Luther King was also assassinated because he fought for the liberty of the citizens. John F. Kennedy was also assassinated similarly. Shri Rajiv Gandhi was assassinated, as my learned friend, Shri Suresh Pachouri has pointed, since there was a security lapse. I would like to submit that a message was sent from a foreign country before the assassination of Shri Rajiv Gandhi, giving information about a possible attack on him in Madras or Delhi. That interception was received by the Intelligence Bureau, but they were not able to read it because it was of 1948 code, cypher code of 1948. And, Shri Rajiv Gandhi was assassinated. If the Intelligence Bureau officials and security forces were more alert and better equipped and were able to read everything, we would not have lost our beloved leader, Shri Rajiv Gandhi. Prior to that, Smt. Indira Gandhi was also assassinated. So, they have been assassinated not on the ground of personal enmity between the family and feudal relationship between one person and other, but for the reason that they fought for the cause of India or for the cause of other nations or for the development of country. There, enmities crept in and they were assassinated. So, in order to safeguard the lives of the Prime Ministers after their retirements and in order to safeguard their family members, this Bill has been brought forward and I wholeheartedly welcome this Bill. Above all, nowadays, we know about the Al Qaeda movement, Jaish-e-Mohammad movement, Lashkar-e-Taiba movement, etc. have fanned throughout the country. Everyday, we feel some sort of fear among the leaders. Leaders are afraid to go out and meet the people. They have been prevented by all these movements. Once a Prime Minister dies, his family members have the same fear in meeting the public. So, under those circumstances, this Act had been brought into force. But, originally it was for five years, then, it was for 10 years and now, it has been reduced to one year. I believe, due to financial constraints and other matters, that step has been taken. But, as my learned friend has pointed out, financial consideration alone should not be the main consideration, but the sacrifices made by the leaders and their families should also be taken into consideration. Sacrifice alone is the most important consideration, not the money, which should be kept in mind before accepting it. As far as the DMK Party is concerned, I support it. As far as Smt. Soniaji is concerned,

finance should not be a problem. This Government should take all measures to provide security to her and to her family members. Thank you, Sir.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu And Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, within the parameters of the Bill, this measure is welcome, excepting to say that the amendment suggested by Shri Pachouri is in the right direction. The nation has paid a high price, say, when Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi and the then Chief Minister of Punjab, Shri Beant Singh, fell martyrs for the sake of the nation. So, we have to be alert on both sides. For this, the measure is welcome. But I would suggest very briefly - there is no time to make a speech - that it should not be an *ad hoc* measure. The whole concept of threat perception has to be institutionalised. As for this measure, these leaders must receive the attention of the nation, through Government, and financial constraints are not relevant to this kind of a situation. But, apart from these leaders, there are individual Members, be it in Parliament of India, or, outside Parliament of India, whose threat perception is not being assessed at proper levels in the Home Ministry. It is embarrassing; but I want to share with this august House that some of us, including me, have a compulsion of the situation or we respond to our conscience, and, we are clear on the whole concept of terror and cross-border insurgency. So, sometimes, we make statements at the spur of the moment and we are left in the lurch. I want to remind the hon. Minister, - he can see the file - I made a strong statement when the massacre of the families of the Jawans took place at Kaluchak, and the same evening I received a threat. And, the next morning, I wrote to the Home Minister, and the Home Ministry did not stir up. I forwarded one or two copies to very important people. Therefore, my contention is that the threat perception of individual Members of Parliament, or, the leaders outside, is being assessed at very junior levels in the Ministry of Home Affairs. Through you, I want to bring this to the notice of the hon. Minister. He must kindly study the file and see my letter. It is not that I am writing now or that I am about to write. Therefore, this threat perception to individual Members of Parliament and outside leaders, who respond to the situation of terror and the cross border insurgency, and who condemn the same, must be assessed at proper levels. Thank you.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I do agree with the spirit of the Bill. Of course, the provision of the

Bill is limited to ex-Prime Ministers and their relatives. And, we have to keep in view the general feeling of the House for national leaders who have threat to their lives, and whose lives are valuable for the overall development and the interest of the nation. As a matter of fact, at the earlier time, when the amendment was made, and now with the present amendment, I see there is a reverse side of it. It can be possible that keeping in spirit with the earlier amendment, a view can be taken within the expiry of the period and the decision is taken. Anyhow, the paramount thought is that we have to protect the national leaders, irrespective of the political party they belong to, and keeping in view the fact that they are indispensable for the overall development of the nation. Therefore, I do agree with the amendment moved by Shri Suresh Pachouri. I think, there should be no difficulty in accepting the amendment, if the hon. Home Minister has the same spirit which he had while replying to the debate that was held in the Lok Sabha about the protection of Shrimati Sonia Gandhi, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and coincidentally happens to be a kith and kin of Shri Rajiv Gandhi. If that spirit is there, why should we not have a positive attitude. So far as the amendment moved by Shri Suresh Pachouri, to make it mandatory, is concerned? So far as the spirit behind this amendment is concerned, the Minister does not have a different view. So, let us make it mandatory. With these words, I support the amendment moved by Shri Suresh Pachouri.

**श्री आर.पी. गोयनका** (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा संदेश गृह राज्य मंत्री जी के लिए है कि वह दस साल, पांच साल से एक साल का जो पीरियड कर रहे हैं, ऐसा बिल लाने से पहले उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। यह क्या बात हुई ? क्या इसको एक साल के लिए आगे नहीं कर सकते थे? क्या पैसे की कमी है या इन्सानो की कमी है या इच्छा की कमी है ? यह सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं।

SHRI I.D. SWAMI : Sir, I am grateful to the hon. Members who have generally shown very great concern for the former Prime Ministers and their immediate family members, and particularly for a family which has suffered a lot. And there is no doubt about it. Not only the hon. Members here, in this august House which is cognizant of this fact and always recollects the ghastly happenings which had taken place in this country, but the whole nation is aware of it. And that is why the hon. Members have been showing the concern that while making any amendment or moving any amendment as hon. Member, Shri Suresh Pachouri has moved we should take into consideration that no risk is taken and no lacuna is left at all. I

can assure this House, through you, Sir, that this amendment Bill is being moved, of course, to bring uniformity and consistency, that from year to year we may go on making assessments. As far as assessment machinery is concerned, there are two Committees - one is a junior group and the other is a senior group - which make an assessment. Sir, annual assessments are made every year regarding threat perception. But some machinery has to be made. All these considerations, that a particular family has suffered a lot and that this nation has suffered a lot - not only a family has suffered but the whole nation has suffered - we have taken care of. It is in writing in our own amendment Bill that if the threat perception is there from any militant organisation and it is grave and continuing, then on the basis of that threat perception the SPG cover would continue. But I also agree with Shri Suresh Pachouri's amendment. So far as the spirit of this amendment is concerned, nobody would have any quarrel about it. The spirit of the amendment will have to be kept in view by any Government, whichever Government may be there. They will have to keep in view the spirit. In the context of the changed circumstances of cross border terrorism, a war, a proxy war, is thrust upon us and sophisticated weapons become available. We have, on the basis of the recommendations of the Group of Ministers and the task force appointed by them, taken a lot of steps in collecting intelligence. One of the Members also mentioned about the Intelligence apparatus. We are having a separate cell in the Ministry of Home Affairs. We are upgrading the whole process of Intelligence collection, and analysis of that Intelligence, in the Home Ministry.

For border management, a separate division is being opened in the Ministry of Home Affairs, under the charge of a full-fledged Secretary, so that all our 15,000 kms. of long border is properly managed and taken care of by having sophisticated equipment, sensors and night vision equipment, etc., and also by recruitment of more people. There is no doubt about it.

But so far as the threat perception in respect of the former Prime Ministers and their family members is concerned, the spirit of the amendment proposed by Shri Pachouri, has to be kept in view and will be kept in view; this, I can assure you. As regards the other things, which have been mentioned so far as the SPG personnel are concerned, their family members are concerned, the other VIPs are concerned, well, there is no doubt, and you will agree, and the whole House will agree, with me, Sir, that after all everybody cannot be provided the SPG cover.

Sir, the SPG was raised in 1988, when this Act was passed, only for the purpose of providing protection to the Prime Minister. These amendments came later in 1991, 1994 and 1999, for protecting the former Prime Ministers and their family members. That was the intention. But alternative arrangements also exist for the safety and security of VIPs and other important people of this country. There is no doubt that everybody wants to avoid any untoward incident involving any VIP or a Minister or an important person or any other leader of this nation.

The hon. Member, Mr. Soz pointed out another aspect. Well, there are many hon. Members and leaders who frequently make statements concerning the unity and integrity of our country. Well, if they also perceive threat, then that threat perception can also be assessed. But when this threat perception has to be assessed, we will have to leave it to some agency; some system has to be evolved. That system already exists. But some suggestions, which have been made by some hon. Members, will be certainly kept in view, because all these decisions are kept under constant review. There is nothing final about it. All these systems evolve with the passage of time, with the experience we gain at different places, with the different Intelligence inputs which reach the Government; all these things are taken into consideration. There can be no doubt on that account also.

So, keeping that in view, and not taking much time of this august House, I will say that it is not the question of money. This country can afford to spend money. Any amount of money can be spent, so far as the security and safety of the VVIPs, the former Prime Ministers, the Prime Minister and other important persons in this country is concerned. This country has the strength and the will-power, this Government has the strength and the will power, to assure full security, not only to VVIPs, not only to important persons or important leaders, but to the whole country. In that direction, the whole country is working, the Government is working, and with the cooperation of the Parliament, we have been making amendments. This is the first time that the Group of Ministers sat. Four Task Forces were appointed. The Task Forces made their recommendations. So, the Group of Ministers sat, and after due consideration and deliberations, a lot of recommendations were made, and those recommendations are being implemented by the Government to ensure a sense of security to the whole nation and specially taking care of the important leaders of this country. There is no doubt about it.

In view of this, I can say that money no consideration. Yes, some Members have asked why we cannot recruit more people, train more people and so on, so far as SPG is concerned, because there is a shortage of personnel there. It is not recruitment or training alone. The SPG has been constituted out of the existing paramilitary forces and State Police forces. They have not been recruited directly, because some experience is needed when you are entrusted with the security of such VVIPs. So, we must have already-trained and experienced people. We are drawing people from the State Police agencies and also from the Central Paramilitary Forces. But, despite our efforts, many people are not coming. Some of the hon. Members mentioned about the safety of their kith and kin; they have also mentioned about their pay-scales, etc. I can assure the hon. Members that they are much better placed now and they feel satisfied. The only thing is that such a hard task is entrusted to them that many people have not been forthcoming. The Government is already trying hard to see that the deficiency which exists in the SPG formations is also made up, as soon as possible.

In view of these submissions of mine, I would request and pray to this House that this Bill may kindly be passed. I specially request hon. Member, Shri Suresh Pachouri, that in view of what I have already stated, and in view of the fact that the Amendment already includes a provision that if a grave threat is there to the family members or the former Prime Minister and it is still continuing - that assessment would be made - it will be continued. If any proof is needed, the proof is there from 1999 onwards, this has always been provided. I hope that keeping in view the country's feelings, keeping in view the sentiments of the House and the hon. Members' sentiments, such a view will always be taken. In view of this, I hope, Mr. Pachouri will not insist on his amendment.

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : अब मैं प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है :

"विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2003" जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):** अब हम विधेयक पर धारावार विचार करेंगे । धारा 2 में एक संशोधन है। माननीय श्री सुरेश पचौरी जी ।

**श्री सुरेश पचौरी** : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत जिम्मेदाराना ढंग से एस.पी.जी. अमेंडमेंड बिल, 2003 के, सैक्शन 2 के संदर्भ में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उससे सहमत होते हुए यह व्यक्त किया है कि उसके पीछे जो भावना निहित है, उसे दृष्टिगत रखते हुए, इसके प्रकाश में न केवल वर्तमान सरकार बल्कि भविष्य की सरकार भी एस.पी.जी. की सुविधा उस परिवार को उपलब्ध कराएगी, जिस परिवार से प्रधानमंत्री रहा हो । उस परिवार और उसके परिवारजनों को आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होना पड़ा हो । इस संदर्भ में उन पर विश्वास करते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं । मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का थ्रेट परसेप्शन काफी हाई है । इसको मद्देनजर रखते हुए और उस परिवार की जो शहादत है, खासतौर से आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियो को रोकने के लिए, उसे दृष्टिगत रखते हुए एस.पी.जी. प्रोवाइड करने में इन बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाएगा । मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

**धारा 2 विधेयक का अंग बनी**

**धारा 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बने ।**

SHRI I.D. SWAMI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

**प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ ।**

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : अब हम कल शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003 की दोपहर 12.30 बजे तक के लिए उठते हैं ।

The House then adjourned at thirty-one minutes past four of the clock till thirty minutes past twelve of the clock on Friday, the 28th February, 2003.

---



MGIPMRND—52RS—24.12.2003.